भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 334

17 मार्च, 2020 को उत्तरार्थ

विषय : मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जारी किया जाना

*334. डा॰ चन्द्र सेन जादौनः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देशभर में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना प्रारम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए जारी नीति दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान इस उद्देश्य के लिए आवंटित निधि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश के विभिन्न स्थानों पर मृदा जांच और अनुसंधान प्रयोगशालाएं तथा चल मृदा जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में भी इस प्रकार की प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने का विचार है?

<u>उत्तर</u>

<u>कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)</u>

(क) से (ड.) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>'मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाने' से संबंधित लोक सभा में दिनांक 17.03.2020 को उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 334 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) एवं (ख) सरकार वर्ष 2015 से मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी) योजना को कार्यान्वित कर रही है ताकि 2 वर्ष के एक चक्र में एक बार देश के सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया जा सके। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मृदा की पोषण स्थिति की जानकारी 12 मानदंडों अर्थात प्राथमिक पोषक तत्व (नाईट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाश), द्वितीय पोषक तत्व (सल्फर), सूक्ष्म पोषक तत्व (बोरोन, जिंक, मैगनीज, आयरन एंड कॉपर) तथा अन्य (पीएच, ईसी एंड आर्गेनिक कार्बन) के आधार पर देने के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य और इसकी उर्वरता में सुधार लाने के लिए उपयोग किए जाने हेतु पोषक तत्वों की उचित मात्रा संबंधी जानकारी प्रदान करता है। चक्र- 1 (2015-17) में 10.74 करोड़ और चक्र- 2 (2017-19) में 11.75 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को वितरित किए गए थे। वर्ष 2019-20 के दौरान, ''मॉडल गांवों का विकास'' नामक एक प्रायोगिक परियोजना 6954 गांवों (एक गांव/राजस्व ब्लॉक) में शुरू की गई है। यहां किसानों की भागीदारी से व्यक्तिगत कृषि जोत आधारित नमूना संग्रह के साथ-साथ जागरूकता अभियान और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सलाह के अनुसार उर्वरकों के प्रयोग पर प्रदर्शन भी सुनिश्चित किए जाते हैं। अभी तक मॉडल ग्रामों में प्रदर्शन के साथ- साथ 14.32 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं।

(ग) वर्तमान वर्ष (2019-20) के दौरान एसएचसी स्कीम के लिए आबंटित निधियों का राज्यवार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) के मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन घटक के अंतर्गत राज्यों के प्रस्तावों/आवश्यकताओं के अनुसार स्थायी एवं सचल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं (एसटीएल) स्वीकृत की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 के दौरान राज्यों के लिए 10845 एसटीएल स्वीकृत की गईं जिनमें 429 स्थायी एसटीएल, 102 सचल एसटीएल, 8752 लघु एसटीएल एवं 1562 ग्राम स्तरीय एसटीएल शामिल हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मृदा नमूनों के परीक्षण के माध्यम से किसानों में मृदा स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1076 लघु मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्वीकृत की हैं।

(ड.) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में पहले से ही 243 स्थायी मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। जिसमें अयोध्या (पूर्व फैजाबाद जिला) में 3 एसटीएल सहित प्रत्येक जिले में एसटीएल है।

अनुबंध

वर्तमान वर्ष (2019-20) के दौरान मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के लिए राज्यवार आबंटन का विवरण:

क्र.सं.	**राज्य**	**राशि (रु. – लाख)**
1	आंध्र प्रदेश	1197.41
2	अरुणाचल प्रदेश	159.07
3	असम	610.81
4	बिहार	1534.95
5	छत्तीसगढ़	239.50
6	गोवा	19.74
7	गुजरात	432.78
8	हरियाणा	228.06
9	हिमाचल प्रदेश	172.76
10	जम्मू और कश्मीर	670.06
11	झारखंड	419.86
12	कर्नाटक	343.15
13	केरल	515.39
14	मध्य प्रदेश	668.65
15	महाराष्ट्र	854.69
16	मणिपुर	100.66
17	मेघालय	59.31
18	मिजोरम	39.18
19	नागालैंड	212.95
20	ओडिशा	638.08
21	पंजाब	201.43
22	राजस्थान	577.76
23	सिक्किम	48.00
24	तमिलनाडु	556.36
25	तेलंगाना	868.12
26	त्रिपुरा	164.13
27	उत्तर प्रदेश	1330.37
28	उत्तराखंड	160.80
29	पश्चिम बंगाल	656.19
30	पुडुचेरी	18.60
31	दादर और नगर हवेली	5.53
32	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	17.74
33	लद्दाख	0.00
	कुल	13722.09